स्टील फ्रेम की दुबारा मरम्मत

साभार : द हिन्दू
22 अगस्त, 2017

श्रीवत्स कृष्णा (आईएएस अधिकारी)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका, शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

नौकरशाहों को पार्श्व प्रवेश, प्रौद्योगिकी और 'प्रदर्शन या विनाश' की संस्कृति को गले लगाने की जरूरत है।

18 वीं शताब्दी के नियमों का उपयोग करते हुए 19वीं शताब्दी की नौकरशाही के साथ 21 वीं सदी की अर्थव्यवस्था को चलाना असंभव है। ''नई भारत'' को भी बुरी नौकरशाही से आजादी की आवश्यकता है, जरूरी नहीं कि सभी नौकरशाही से, लेकिन किसी भी राज्य के लिए नियमों के कुछ सेटों द्वारा लोगों के कुछ समूह द्वारा चलाने की आवश्यकता होती है, अब चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकार ले। जब हम कहते हैं कि सभी नौकरशाही को समाप्त कर देना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम भाई-भतीजावाद, राजनीतिकरण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी का आरोप लगाते हैं और इसमें सुधार के लिए एक अंपायर और परिवर्तन करने के लिए एक मजबूत उत्प्रेरक की मांग करने लग जाते हैं, लेकिन इसमें भी सिविल सेवा का नाम सबसे पहले आता है।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न

1. क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है? समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये। (2014)

सिविल सेवाओं में तीन मौलिक परिवर्तन लाने की जरूरत है, जिनमें से कुछ नए वितरण के तहत पहले से ही चल रहे हैं। सबसे पहले, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत विशिष्ट खंड अक्षमता और / या भ्रष्टाचार के आधार पर अधिकारियों पर पाबन्दी लगाते हैं। हांलाकि, ये नियम हमेशा नियम पुस्तिका में ही मौजूद रहे, लेकिन वर्तमान सरकार ने जनता के हित में इसका इस्तेमाल करने का साहस दिखाया और अधिक जल्द ही इसे और बेहतर बनाने के लिए और नियमों को शामिल किया जायेगा। काले भेड़ अर्थात दोषियों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक तिरस्कार के साथ घर भेज देना चाहिए।

पार्श्व प्रविष्टि

दूसरा, उच्च नागरिक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ चेतावनियों के साथ प्रशासन की सभी विफलताओं के लिए एक औषधि के रूप में पार्श्व प्रवेश करना केवल असफलता को प्रेरित करेगा, क्योंकि इतिहास सबसे निपुण निजी क्षेत्र के पेशेवरों सरकार के अंदर असफल रहे हैं, ऐसे उदाहरण से भरा पड़ा हैं। हमें निश्चित रूप से यह नहीं भूलना चाहिए कि हसमुख आडिया, जिन्होंने हमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रदान किया, परमेशवर अय्यर जो स्वच्छता का प्रबंधन करते हैं, अरुणा सुंदरराजन जिन्होंने हमें डिजिटल इंडिया दिया, संजय मित्रा जो राजमार्ग से जुड़े हुए हैं, एस. जयशंकर जो भारत को वैश्विक मानचित्र पर दर्शाते हैं, अनिल स्वरूप जो कोयले के नीलामी का नेतृत्व करते हैं, रीता तेवतिया जो जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) का नेतृत्व करते हैं और ''मेक इन इंडिया'' उत्पादों को बढ़ावा देती हैं, इनमें से प्रत्येक ने विभिन्न सेवाओं से अपने सिविल सेवकों की टीम के साथ और प्रधानमंत्री कार्यालय का पूरा नेतृत्व जो उपरोक्त सभी की देखरेख और उत्प्रेरित करता है, पार्श्व प्रवेश के माध्यम से सरकार में नहीं आया था। इसके विपरीत, पार्श्व की प्रविष्टि ने एक पायलट भी तैयार किया है जिसे एक राज्य में कैबिनेट सचिव के रूप में नामित किया गया था, लेकिन वे अपने आप से बाहर हो गये और विचारशील अर्थशास्त्री सरकार के अंदर नेताओं के समक्ष विपत्तियों से घिर गये।

देखा जाये तो, इसकी बहुत कम संभावना है कि एक निजी क्षेत्र के पेशेवर नागरिक सेवाओं को 'करियर' के रूप में देखेंगे, इनका कहना हैं कि मामूली मुआवजा और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दों को 10-15 साल दिए जाते हैं जो अक्सर मापन योग्य इनपुट और परिणामों के खिलाफ होते हैं। इससे पहले 'लाल बत्ती' (red beacon) प्रमुख आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे यह खत्म होता जा रहा है। पार्श्वी प्रविष्टि, सरकार के प्रमुख पदों में अपने लोगों को रखकर शक्तिशाली कॉर्पोरेट समूहों की संभावना और जोखिम को बढ़ता है। हालांकि, निर्णय लेने की योग्यता की गंभीर कमी या सरकार के कुछ वरिष्ठ नेतृत्वों में व्याप्त कमी के सन्दर्भ में विचार किया जाए तो पार्श्व प्रवेश वास्तव में सुशासन के लिए आवश्यक मालूम पड़ता है।

पार्श्व प्रवेश शुरू करने के साथ-साथ एक अन्य नियम को शामिल करने की भी आवश्यकता है, जिसमें यदि कोई 15 साल बाद आईएएस / आईआरएस / आईपीएस / आईएफएस में उपयुक्त नहीं पाया जाता है, यानी संयुक्त सचिव स्तर पर, तो उन्हें गैर-महत्त्वपूर्ण पदों से हटा दे या उन्हें जीवन-काल पेंशन देकर उन्हें घर भेज दे।

दोहन प्रौद्योगिकी

तीसरा बड़ा कदम यह होना चाहिए कि हर प्रमुख बिंदु पर अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी को लागू करना होगा, जिससे एक नागरिक सरकार के साथ संपर्क स्थापित कर सकने में सक्षम हो सकेगा। आज कृत्रिम बुद्धि (एआई) अर्थात आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के साथ, आईपी सॉफ्ट (IPsoft) जैसे वैश्विक प्रौद्योगिकी यू.के. और यू.एस. में नागरिक सेवाओं को वितरित करने के लिए आभासी सहायकों का उपयोग करता है। सरकारी सेवा वितरण के संदर्भ में, संज्ञानात्मक बुद्धि इसे अधिक श्रेष्ठता, सटीकता, स्थिरता और मनुष्य की तुलना में कम लागत पर कार्यों को संभव बना सकती है। सरकारी सेवाओं में एआई को शुरू करने के लिए समय आ गया है, जिसमें पासपोर्ट, लाइसेंस, बिल्डिंग परमिट, सर्टिफिकेट इत्यादि जैसी सरकारी सेवायें शामिल है, जहां यह नागरिकों के साथ प्राकृतिक भाषा में संवाद करते हुए हैं प्रक्रिया अनुपालन को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज 70 वर्ष पूरे होने के बाद भारत को बुरे नौकरशाही और अंतहीन प्रक्रियाओं और अर्थहीन रूपों से स्वतंत्रता की आवश्यकता है, हांलाकि, ''अच्छी'' नौकरशाही से हो यह जरूरी नहीं, जो हर देश में प्रणाली और समय सकारात्मक बदलाव का अग्रदूत रहा है।

इससे संबंधित तथ्य

- पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग ने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने का सुझाव दिया है।
- नीति आयोग ने शासन तंत्र में विशेषज्ञों को जगह देने की भी सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो पेशेवर नौकरशाही में कॉम्पिटीशन का माहौल बनेगा।

सिविल सर्विस और ताकतवर हो

- हाल में पब्लिक हुई थ्री ईयर एक्शन प्लान एजेंडा पर तैयार की गई ड्राफ्ट रिपोर्ट में नीति आयोग ने साल 2018-19 के आखिर तक सरकार से जुड़े कामों को पूरी तरह डिजिटाइज करने का लक्ष्य भी तय किया है।
- इसमें कहा गया है कि सिविल सर्विस सरकार की बैकबोन है और इसे ताकतवर बनाने के लिए तुरंत जरूरी निर्णय लिए जाने चाहिए।
- इस मामले में लगातार हाई लेवल परफॉर्मेंस तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जब इसकी समीक्षा कर अच्छे परफॉर्म करने वालों को रिवार्ड मिले और कमजोर काम को हतोत्साहित किया जाए।

ब्यूरोक्रेसी में पॉजिटिव साइड इफेक्ट होगा

- नीति आयोग ने ड्राफ्ट रिपोर्ट के जरिए कहा कि आज अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं का मतलब है कि नीति निर्माण एक विशेष काम है। इसलिए जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों को आधी-आधूरी एंट्री देकर सिस्टम में शामिल किया जाए।
- इस तरह की एंट्री का पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी होगा, क्योंकि इससे ब्यूरोक्रेसी में कॉम्पिटीशन बढ़ेगा।

सेक्रेट्री रैंक के अधिकारियों को लंबा समय मिले

- रिपोर्ट में सरकारी विभागों में सेक्रेट्री रैंक के अधिकारियों के लंबे कार्यकाल की वकालत की गई है। अभी जब अधिकारियों को रिटायरमेंट होने में कुछ समय बचता है तो उन्हें एडिशनल सेक्रेट्री से सेक्रेट्री लेवल पर प्रमोट किया जाता है। बता दें कि साल 2017-18 से 2019-20 के लिए एक्शन एजेंडा का प्रस्ताव नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में 23 अप्रैल को बांट दिया गया है। राज्यों के मुख्यमंत्री काउंसिल के सदस्य हैं।

मोटी सैलरी भी देगा नीति आयोग

- नियुक्ति को निजी सेक्टर के लिए खोलने के लिए साथ ही नीति आयोग सैलरी में भी बड़े सुधार की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक वरिष्ठ सलाहकार के पद पर 3.64 लाख रुपये मासिक का पैकेज दिया जाएगा।
- इसके अलावा सलाहकार के पद पर भी 2.88 लाख रुपये का पैकेज दिए जाने का प्रस्ताव है। इन पदों पर नियुक्त होने वाले लोगों को अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं हासिल होंगी।
- यह नियुक्त 5 साल के लिए कॉन्ट्रेक्ट पर होगी, जिसे 7 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

संभावित प्रश्न

''नीति आयोग ने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने का सुझाव दिया है। साथ ही आयोग का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो पेशेवर नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा।'' इस कथन के सन्दर्भ में नीति आयोग द्वारा लिए गए निर्णय की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322
GS World